(ii) Need to set up an electronic telephone factory in Bhubaneswar.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): The electronic industry is conspicuously absent in the eastern region, and particularly in Orissa. Government of India had taken a decision to remove regional imbalance in respect of setting up of electronic industry in the country. The location of the Electronic Telephone Factory at Bhubaneswar will go a long way in removing the regional imbalance.

Bhubaneswar is ideally suited for the location of this telephone industry. It has not only got all infrastructural advantages, but its clear climate is immensely suitable for setting up any type of electronic industry. The State being industrially backward in general, and with regard to the electronic industry in particular, the setting up of this industry at Bhubaneswar will help in the establishment of a large number of ancillary and downstream electronic units around it, and help the growth of industrialization in the nucleus industrial complex in the Chandaka area.

The Government of Orissa has been pressing for the setting up of a unit of electronic telephone industry in the State for a long time. In view of this, I urge upon the Government of India to take an early decision and expedite the setting up of an electronic telephone industry at Bhubaneshwar forthwith.

(iii) Relief for people affected by subsidence of Jharia Town.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): The danger of subsidence is haunting over the great old coal town Jharia since 22nd March 1982 when a part of the town suddenly collapsed in the early morning, as the ground subsided due to the blasting and under-ground fire of the colliery. At least 40 houses were affected, and 14 levelled to the ground. As it was in the morning, people could come out quickly; otherwise, it would have been a bad disaster with many casualties. Hundreds of people, mostly of the minority community and Harijans, have become homeless, and are now on the streets without any rehabilitation and care, creating a serious situation.

Both the Bharat Coking Coal Ltd. which owns the collieries in these areas, and the Director-General of Mines Safety which supervises the safety aspect, expressed their surprise at this incident, as their official report did not show the progress of underground fire in the coal-seam upto the heart of the Jharia town.

The incident on Monday morning has created panic and terror in the town. BCCL was already talking of evacuating the Jharia town, to extract the prime coking coal under it, and the subsidence has created suspicion whether this was a process adopted by BCCL deliberately, to evacuate Jharia town, as there was a report that the subsidence was due to faulty mining, which had spread fire underground, instead of controlling it. Government must probe into the whole incident of subsidence, compensate and rehabilitate those whose houses collapsed. If the entire Jharia town has become really unsafe due to underground fire, then there should be a systematic arrangement to shift the town with full arrangement for rehabilitation, to avoid a catastrophe which may happen any time, endangering the lives of thousands.

(iv) Need for giving possession of Land allotted to Harijans of Bawana Village in Delhi.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बवाना नाम का छोटा-सा ग्राम है जहां काफी संख्या में भूमिहीन जाटव भाई रहते हैं। 8 फरवरी, 1981 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने बवाना के भूमिहीन हरिजनों को मकान बनाने के लिए 120 वर्ग गज के प्लाटों का आवंटन किया था। इस आवंटन के बदले में भूमिहीनों से 5 पैसे प्रति वर्गगज वार्षिक पट्टे के आधार पर 55 रुपया भी वसूल किया गया और लोगों को उसकी रसीदें भी दी गईं।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह बहुत आश्चर्य तथा खेद का विषय है कि जिन हरिजनों को भूमि के पट्टे दिये गये थे उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है । एक पंचायत मेम्बर ने अवश्य ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम काफी जमीन कर ली है और उन्हें जमीन का कब्जा भी मिल चुका है । इस पंचायत सदस्य के प्रभाव से गांव की फालतू जमीन एक ही परिवार के सदस्यों के उपयोग में आ रही है । यहां तक कि हरिजन भाइयों के श्मशान को भी साजिश करके बेच दिया गया है। गांव की फालतू जमीन पर नाजायज कब्जा करके उस पर ईंटों के भट्टे लगा दिये गये हैं ।

मेरी मांग है कि बवाना गांव में भूमि वितरण के नाम पर हरिजन भाइयों के साथ जो मखौल किया गया है उसकी उच्चस्तरीय जांच की जाय । जिन हरिजनों को भूमि का आवंटन किया गया और जिनसे रुपये भी वसूल किये गये उन्हें अविलम्ब भूमि का कब्जा दिया जाय । गांव में इस अन्याय के विरुद्ध बड़ा रोष व्याप्त है । यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है ।

(v) Alleged retrenchment of Labourers working on famine relief works in Bhilwara, Rajasthan.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान) जिले की आबादी 12.50 लाख है और 3-4 साल से भयंकर अकाल से ग्रस्त है । पिछले साल भी इस जिले में अकाल था तब एक लाख से ज्यादा लोग अकाल राहत पर लगे हुए थे । इस वर्ष भी करीब 70 हजार लोग तारीख 14-3-82 तक अकाल राहत पर लगे हुए थे ।

अकाल राहत प्रोग्राम के अधीन लोगों को काम दिया जाता है । लेकिन हाल ही में 15 हजार लोगों को काम से छुट्टी दे दी गई है, जिससे कि भूख से पीड़ित लोगों की पीड़ा में और भी अधिक वृद्धि हो गई है । वह काम की तलाश में इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं । इस भयंकर महंगाई के समय काम से अलग करना गरीब के साथ भयंकर अन्याय है । गरीबी की सतह से नीचे तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को ऐसे भयंकर अकाल के समय में काम से अलग करना गरीब के प्रति अन्याय के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सस्ते अनाज की भी उचित व्यवस्था नहीं, न पीने के पानी की व्यवस्था है कुछ क्षेत्रों में जहां प्रभावशाली लोग हैं वहां जरूरत से ज्यादा सामान जुटा दिए गए और बकाया सारे क्षेत्र में पीने के पानी का भारी अभाव है और ज्यों-ज्यों गर्मी का मौसम आएगा त्यों-त्यों पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी । समय रहते पीने के पानी की व्यवस्था न की गई तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

अंत में मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की सरकार व जिलाधीश भीलवाड़ा ने जिन 15 हजार मजदूरों को काम किया है, उनको तुरन्त काम पर वापस लगाया जाए व अनाज व पीने के पानी की व्यवस्था की जाए । जिन सरकारी अधिकारियों ने यह अन्याय किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ।

(vi) Need for permanent anti-flood measures in certain Eastern districts of Uttar Pradesh.

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी करनाली (मालूबाग) योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन् पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे 16 जिले जो घाघरा एवं राप्ती नदियों की चपेट में प्रत्येक वर्ष आते हैं और प्रत्येक वर्ष प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपये धन-जन की रक्षा एवं भवनों की मरम्मत हेतु व्यय करती है । किन्तु इससे अस्थाई रूप से कुछ क्षणिक मदद मिल जाती है । ये सारी आपदाएं